पटना उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार में

2024 का सिविल रिट क्षेत्राधिकार मामला सं.10496

==========

संजय कुमार, पिता - महेश्वर चौधरी, निवासी-जय महाराजा वर्क्स, कलमबाग चौक, थाना.-काजी मोहम्मदपुर, मुजफ्फरपुर, जिला-मुजफ्फरपुर, बिहार।

... ... याचिकाकर्ता

बनाम

1. बिहार राज्य।
2. विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति, बिहार, राजभवन, पटना।
3. अपर मुख्य सचिव, शिक्षा विभाग, बिहार सरकार, पटना।
4. राज्यपाल के प्रधान सचिव-सह-कुलपति, राजभवन, पटना।
5. उपकुलपति, भीम राव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार।
6. कुलसचिव, भीम राव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार।
7. डॉ. अपराजिता कृष्णा, कुलसचिव, भीम राव अम्बेडकर, बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर, बिहार।

... ... प्रतिवादीगण।

==========

उपस्थिति :

याचिकाकर्ता के लिए	:	श्री धनंजय कश्यप, अधिवक्ता
		श्री ज्ञान शंकर, अधिवक्ता
राज्य के लिए	:	स्थायी सलाहकार-4
प्रतिवादी संख्या 2 और 4 के लिए	:	श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, वरीय अधिवक्ता
		श्री राजीव रंजन कुमार पांडे,अधिवक्ता
बी.आर.ए.बी. विश्वविद्यालय के लिए	:	श्री बिन्धयाचल राय, अधिवक्ता
प्रतिवादी सं.7 के लिए	:	श्री संतोष कुमार, वरीय अधिवक्ता
		श्री मधुरेंद्र शर्मा, अधिवक्ता
		श्री पवन कुमार, अधिवक्ता

श्री उत्सव, अधिवक्ता

==========

अधिनियम/धाराएं/नियम:

- *बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धाराएं 7, 15*

संदर्भित मामले:

- *भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य, एआईआर 1987 एससी 1023 में रिपोर्ट किया गया*
- *राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, एआईआर 2021 एससी 2114 में रिपोर्ट किया गया*
- *मोहन सिंह और अन्य बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण और अन्य। (1997) 9 एससीसी 132 में रिपोर्ट की गई*
- *नजीर अहमद बनाम किंग एम्परर, 1936 एससीसी ऑनलाइन पीसी 41*
- *चेरुकुरी मणि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, (2015) 13 एससीसी 722*
- *व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार, मुंबई (1998) 8 एससीसी 1 में रिपोर्ट की गई*

रिट याचिका- *वह अधिसूचना रद्द करने के लिए दायर की गई, जिसके तहत याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद से हटा दिया गया और एक प्रतिवादी को रजिस्ट्रार नियुक्त किया गया, जबकि वह इस पद के लिए कानून द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यता नहीं रखती थीं।*

निर्णय- *रजिस्ट्रार पद पर नियुक्ति और पदमुक्ति एक निर्धारित प्रक्रिया के तहत की जानी चाहिए और यह जल्दबाजी, अपारदर्शिता और व्यक्तिनिष्ठता के आधार पर नहीं हो सकती। (पैरा 28)*

न्यायालय को प्रतिवादियों की इस दलील में कोई दम नहीं दिखता कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया था और इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन आवश्यक नहीं था। इस दलील को खारिज करने का स्पष्ट कारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8 और धारा 15(3)(सी) से निकलता है। (पैरा 29)

याचिकाकर्ता को उनके प्रदर्शन के मूल्यांकन के आधार पर रजिस्ट्रार पद से हटाया गया है, और इस कृत्य को केवल "मुक्त करने" या "स्थानांतरण" जैसे साधारण शब्दों के प्रयोग से ढका नहीं जा सकता। यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15(3)(c) के तहत स्थानांतरण का मामला निश्चित रूप से नहीं बनता। (पैरा 30)

यदि किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार पद से हटाने की एक निर्धारित प्रक्रिया है, तो इस प्रक्रिया को केवल यह कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता कि यह कुलाधिपति के आदेशों पर लागू नहीं होती, बल्कि यह केवल कुलपति की सिफारिशों पर लागू होती है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाए, तो यह प्रक्रिया मात्र औपचारिकता बनकर रह जाएगी, जिसे सुविधानुसार अपनाया या नकारा जा सकता है। इस प्रक्रिया को अनिवार्य मानने का एक और कारण यह है कि यह प्रक्रिया कुलाधिपति को एक निष्कर्ष तक पहुंचाने में सहायता करती है कि क्या किसी व्यक्ति को रजिस्ट्रार पद से हटाया जाना चाहिए। यह निर्णय आरोपों, उनके उत्तर और सहायक प्रमाणों पर विचार करके लिया जाना चाहिए ताकि एक सूचित निर्णय लिया जा सके, जिससे प्रभावित व्यक्ति को भी यह अवसर मिले कि वह प्रस्तुत सामग्री में त्रुटियां दिखाकर कुलाधिपति के समक्ष अपील कर सके। यदि इस प्रक्रिया को कुलाधिपति के आदेशों पर लागू नहीं माना जाता, तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और प्रभावित व्यक्ति किसी भी प्रभावी कानूनी उपाय से वंचित रह जाएगा। (पैरा 34)

याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार पद से हटाना कुलाधिपति के कार्यालय द्वारा जारी पत्र की शर्तों के तहत निर्धारित प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना में किया गया है और इसलिए यह विधि सम्मत नहीं है। साथ ही, प्रतिवादी की नियुक्ति, जो कि इस पद के लिए अयोग्य थीं, बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 में निहित अनिवार्य वैधानिक आवश्यकताओं का घोर उल्लंघन है और यह विधि की दृष्टि में अस्थिर है। (पैरा 41)

रिट याचिका स्वीकार की जाती है। (पैरा 42)

==========

पटना उच्च न्यायालय का निर्णय आदेश

==========

समक्षः माननीय न्यायमूर्ति श्री अंजनी कुमार शरण

सी. ए. वी. निर्णय

तारीखः14-02-2025

पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं को सुना गया।

2. वर्तमान रिट याचिका निम्नलिखित राहतों की मांग करते हुए दायर की गई है:

"(i) प्रतिवादी सं. 4 के हस्ताक्षर द्वारा निर्गत ज्ञापांक-बी. एस. यू. (कुलसचिव)-06/2023-948 जी. एस. (आई) दिनांक 18.06.2024 में

निहित अधिसूचना को निरस्त करने के लिए इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, जिसके तहत माननीय कुलाधिपति ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (आज तक के संशोधन के अनुसार) की धारा 15 के तहत उनमें निहित शक्ति के तहत प्रतिवादी संख्या 7 को बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद पर नियुक्त किया है, इस तथ्य के बावजूद कि उनके पास भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलसचिव के पद को धारण करने के लिए विधि के तहत निर्धारित आवश्यक योग्यता नहीं है और उसने याचिकाकर्ता को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन किए बिना और याचिकाकर्ता को कोई सूचना दिए बिना और निर्गत दिशा-निर्देशों का पालन किए बिना, भीमराव अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलसचिव के पद से हटा दिया है। इस संबंध में राज्यपाल सचिवालय द्वारा ज्ञापांक-बी. एस. यू.-45/2019-844 जी. एस. (आई) दिनांक 27.05.20 (अनुलग्नक-पी./11) के माध्यम से आदेश निर्गत किया गया है।

(ii) भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्रार के रूप में नए पदधारी (अर्थात डॉ. अपराजिता कृष्णा) के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन संख्या बी/1612 दिनांक 19.06.24 में निहित अधिसूचना को रद्द करने के लिए उचित रिट आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, जिसके द्वारा यह अधिसूचित किया गया है कि प्रतिवादी संख्या 7 ने 19 जून 2024 की दोपहर से भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्रार के कार्यालय का प्रभार इस आधार पर ग्रहण कर लिया है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 7 के पास रजिस्ट्रार का पद धारण करने के लिए बुनियादी और अपेक्षित योग्यता नहीं है और बीआरए के रजिस्ट्रार के पद पर उनकी नियुक्ति बिहार विश्वविद्यालय बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (जैसा कि आज तक संशोधित है) की धारा 15 में उल्लिखित शर्तों और प्रक्रियाओं के अनुरूप नहीं की गई है।

(iii) आगे, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलसचिव के हस्ताक्षर के तहत निर्गत ज्ञापांक- बी/1620 दिनांक 20.06.24 में निहित कार्यालय आदेश को निरस्त करने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी करने के लिए, जिसके द्वारा और जिसके तहत प्रतिवादी संख्या 7 ने बिना किसी भी अधिकार क्षेत्र के याचिकाकर्ता को बी. आर.

ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलसचिव के पद से मुक्त कर दिया है।

(iv) तथा, इस माननीय न्यायालय द्वारा बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्रार के हस्ताक्षर से जारी ज्ञापन संख्या बी/1620 दिनांक 20.06.24 में निहित कार्यालय आदेश को रद्द करने के लिए उचित रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जा सकते हैं, जिसके तहत विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पद से अवैध रूप से मुक्त होने के बाद, पूरी तरह से दुर्भावनापूर्ण, अवैध और मनमाने तरीके से याचिकाकर्ता को उसके मूल और मूल पदस्थापन स्थान यानी विश्वविद्यालय अर्थशास्त्र विभाग, सामाजिक विज्ञान ब्लॉक, बीआरए बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में वापस करने के स्थान पर आर.एन. कॉलेज, हाजीपुर में पदस्थापित किया गया है।

(v) तथा इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा बिहार विश्वविद्यालय, राजभवन, पटना (प्रतिवादी संख्या 2 एवं 4) के कुलाधिपति कार्यालय को उचित रिट, आदेश एवं निर्देश जारी किए जाएं कि वे इस माननीय न्यायालय के समक्ष मूल संबंधित अभिलेख प्रस्तुत करें, ताकि यह पता चल सके कि किस आधार पर याचिकाकर्ता को बिना कोई नोटिस दिए रजिस्ट्रार के पद से हटाया गया है तथा क्या रजिस्ट्रार के पद के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 7 की नियुक्ति में बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15 एवं धारा 10 में वर्णित विधि की उचित प्रक्रिया तथा न्यायालय द्वारा प्रतिपादित संबंधित विधियों एवं विधि के प्रावधानों का पालन किया गया है तथा यदि यह अवैध एवं विधि के विरुद्ध पाया जाता है तो उस स्थिति में बीआरए विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पद से याचिकाकर्ता को हटाने की पूरी प्रक्रिया को निरस्त कर दिया जाएगा। बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर और बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्रार के पद के विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 7 की नियुक्ति को रद्द किया जा सकता है और परिणामस्वरूप याचिकाकर्ता को बी.आर.ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के रजिस्ट्रार के पद पर बहाल किया जा सकता है।

(vi) और मामले के दिए गए तथ्यों के तहत इस माननीय उच्च न्यायालय द्वारा कोई अन्य उपयुक्त रिट, आदेश या निर्देश जारी किए जा सकते हैं।

3. वर्तमान मामले के संक्षिप्त तथ्य यह हैं कि याचिकाकर्ता को 20.11.2002 पर व्याख्याता (अर्थात सहायक प्राध्यापक) के पद पर नियुक्त किया गया था। उन्हें डब्ल्यू.ई.एफ.28.06.12 से रीडर (सह-प्राध्यापक) के पद पर पदोन्नत किया गया और उसके बाद उन्हें डब्ल्यू.ई.एफ.28.06.2020 से प्राध्यापक के पद पर पदोन्नत किया गया। इसके बाद, याचिकाकर्ता को राज्यपाल सचिवालय, बिहार द्वारा जारी अधिसूचना के माध्यम से बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर के कुलसचिव के रूप में नियुक्त किया गया, जैसा कि ज्ञापांक-बीएसयू (कुलसचिव) 27/2017-815 जीएस (आई) दिनांक 05.06.2023 में निहित है। याचिकाकर्ता ने संबंधित अधिकारियों की संतुष्टि के लिए बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय (इसके बाद 'विश्वविद्यालय' के रूप में संदर्भित) के कुलसचिव के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करना शुरू कर दिया। अचानक, याचिकाकर्ता को बिना किसी पूर्व सूचना या सुनवाई के, प्रतिवादी सं.4 ने एक अधिसूचना जारी की, जैसा कि ज्ञापन सं.-बी एस यू (कुलसचिव)-06/2023-948 जीएस (आई) दिनांक 18.06.2024 में निहित है, जिसके द्वारा प्रतिवादी सं. 7 को कुलसचिव नियुक्त किया गया। 19.06.2024 को, प्रतिवादी सं.7 ने विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद का कार्यभार संभाला। एक कार्यालय आदेश, 20.06.2024 को जैसा कि ज्ञापांक- बी/1620 दिनांक 20.06.2024, में निहित है, प्रतिवादी सं.7 द्वारा निर्गत किया गया था जिसके तहत याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद से मुक्त कर दिया गया था, और उसे आर. एन. कॉलेज, हाजीपुर में तत्काल प्रभाव के साथ नियुक्त किया गया।

4. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धनंजय कश्यप प्रस्तुत करते हैं कि याचिकाकर्ता कुलसचिव के पद से मुक्त करने की आड़ में ज्ञापांक- बी/1620 दिनांक 20.06.2024 के माध्यम से उन्हें विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद से बर्खास्त कर दिया गया था। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि ज्ञापांक- बी/1620 दिनांक 20.06.2024 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के पूर्ण उल्लंघन और किसी भी व्यक्ति को कुलसचिव के पद से पर्यवसित करने के लिए निर्धारित प्रक्रिया का घोर उल्लंघन करते हुए निर्गत किया गया है जैसा कि पत्र संख्या- बीएसयू (वीसी)-45/2019 दिनांक 27.05.2020 में निहित है।

5. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस अदालत का ध्यान पत्र सं. बीएसयू (वीसी)-45/2019 दिनांक 27.05.2020 की ओर आकर्षित किया है जो इस प्रकार है,

> *यह देखा गया है कि कुलपति सचिवालय में विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति समाप्त करने के लिए कुलपति से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं, जिन्हें माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से नियुक्त किया गया*

है। इस संबंध में मुझे यह सूचित करने का निदेश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 9(7)(ii) तथा पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (अद्यतित संशोधित) की धारा 10 की उपधारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, समुचित विचार-विमर्श के पश्चात, प्राकृतिक न्याय के हित में यह आदेश दिया है कि यदि बिहार के किसी विश्वविद्यालय का कुलपति अपने विश्वविद्यालय में किसी अधिकारी, जिसे माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से नियुक्त किया गया है, जैसे कि वित्तीय सलाहकार, कुलसचिव, वित्त अधिकारी आदि के कार्यकलापों से संतुष्ट नहीं है तथा ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त करना विश्वविद्यालय के शैक्षणिक या प्रशासनिक हित में समझता है, तो उसे सर्वप्रथम उक्त अधिकारी से स्पष्टीकरण/कारण बताओ मांगना चाहिए तथा उसके विरुद्ध आरोपों का विवरण प्रस्तुत करना चाहिए। स्पष्टीकरण/कारण बताओ प्रस्तुत करने के लिए समय, जो सामान्यतः 7 दिन से कम नहीं होना चाहिए (जब तक कि यह बहुत जरूरी मामला न हो)। इसके बाद, यदि कुलपति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण/कारण बताओ से संतुष्ट नहीं हैं, तो वे अधिकारी की नियुक्ति समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव भेज सकते हैं, साथ ही अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण/कारण बताओ पर अपनी टिप्पणी और माननीय कुलाधिपति के आदेश के लिए की जाने वाली कार्रवाई के संबंध में स्पष्ट सिफारिश भी भेज सकते हैं।

6. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान उपरोक्त पत्र की ओर आकर्षित किया है जिसमें कहा गया है कि कुलसचिव के पद से किसी भी व्यक्ति को हटाने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान की गई है जो कारण परीक्षा जारी करके और स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने के लिए एक उचित समय प्रदान करके प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करना अनिवार्य करती है, हालांकि, याचिकाकर्ता के पर्यवसान के मामले में, यह स्वीकार किया जाता है कि याचिकाकर्ता को कुलसचिव के पद से हटाने का आदेश पारित करने से पहले याचिकाकर्ता को कोई पूर्व सूचना, कारण बताओ नोटिस या सुनवाई का कोई अवसर निर्गत नहीं किया गया था, इसलिए, दिनांक 20.06.2024 का आक्षेपित आदेश इसके अनुरूपता में नहीं है। पत्र सं. बी. एस. यू. (वी. सी.)-45/2019 दिनांकित 27.05.2020 में निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूपता में नहीं है और यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का भी उल्लंघन है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धनंजय कश्यप आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी सं.7 की नियुक्ति कुलसचिव के पद पर बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 (इसके बाद 'विश्वविद्यालय अधिनियम' के रूप में संदर्भित) की धारा 15 का पूरी तरह से उल्लंघन है। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादी सं.7 के पास कुलसचिव के पद पर नियुक्ति के लिए अपेक्षित योग्यता नहीं है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15 में कुलसचिव के पद के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी भी विश्वविद्यालय से नामों का एक पैनल मांगे जाने का प्रावधान है, लेकिन वर्तमान मामले में, माननीय कुलाधिपति ने विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15 के तहत किसी भी नाम की मांग नहीं की है, और इस प्रकार नियुक्ति विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15 के तहत अनिवार्य प्रक्रिया के विपरीत है।

8. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने इस न्यायालय का ध्यान मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत किए गए दिनांक 31.12.2006 पत्र और संकल्प संख्या 15/डी 1- की ओर आकर्षित किया है। मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 01/09 अंश 2 उ० शि० 2693 दिनांक 27.08.2009 में प्रस्तुत किया गया है कि कुलसचिव पद के लिए अनिवार्य पात्रता मानदंड *"रु 7000 और उससे अधिक के एजीपी में सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या रु 8000 और उससे अधिक के एजीपी में 8 साल की सेवा के साथ शैक्षिक प्रशासन में अनुभव के साथ सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवा"* शामिल हैं। , हालांकि, प्रतिवादी सं.7 उपरोक्त मानदंडों को पूरा नहीं करने के बावजूद नियुक्त किया गया है।

9. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद से अवैध रूप से हटाने के बाद, याचिकाकर्ता को आर. एन. कॉलेज, हाजीपुर में तैनात किया गया है, जो मुख्यालय से लगभग 60 किलोमीटर दूर है और विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग, बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय, मुजफ्फरपुर में उनकी नियुक्ति के मूल स्थान से 2010 से याचिकाकर्ता की नियुक्ति का मूल स्थान है, जो विश्वविद्यालय द्वारा अपनाई जाने वाली सामान्य कार्य प्रणाली के विपरीत है। यह आगे प्रस्तुत किया जाता है कि आर. एन. कॉलेज, हाजीपुर में याचिकाकर्ता की नियुक्ति तर्क से रहित है और पूर्वाग्रह को दर्शाती है क्योंकि आर. एन. कॉलेज, हाजीपुर में याचिकाकर्ता की

नियुक्ति के तुरंत बाद, दो शिक्षकों को विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्र विभाग में नियुक्त किया, जो याचिकाकर्ता से कनिष्ठ हैं। इस प्रकार एक ओर याचिकाकर्ता को हटा दिया गया है और दूसरी ओर दो नए व्यक्तियों की नियुक्ति की गई है।

10. प्रतिवादी 2 और 4 की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, विद्वान वरीय अधिवक्ता, श्री राजीव रंजन पांडे,विद्वान अधिवक्ता द्वारा सहायता प्रदान की गयी, प्रतिवादी सं.2 और 4,अर्थात माननीय कुलपति की ओर से उपस्थित होकर मुख्य रूप से दो आधारों पर याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया है।

11. अपना पहला आधार उठाते हुए, श्री जनार्दन प्रसाद सिंह, विद्वान वरीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि रिट याचिका पूरी तरह से गलत धारणा है क्योंकि याचिकाकर्ता को "पर्यवसित" नहीं किया गया है, जबकि याचिकाकर्ता को विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 15 (3) (सी) के तहत निहित शक्तियों के आधार पर "स्थानांतरित" किया गया है और इस तरह इससे कोई दंडाभाव नहीं जुड़ा है। अपने दूसरे आधार को आगे बढ़ाते हुए, वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि स्थानांतरण का आदेश माननीय कुलाधिपति द्वारा याचिकाकर्ता के साथ-साथ बिहार के अन्य विश्वविद्यालयों के कुलसचिवों के निष्पादन मूल्यांकन के बाद किया गया है और विश्वविद्यालयों के शैक्षणिक और प्रशासनिक हित में कुलसचिवों को बदलना वांछनीय पाया गया और इसलिए, याचिकाकर्ता को कुलसचिव के पद से मुक्त कर दिया गया था।

12. प्रतिवादी संख्या 5 और 6, अर्थात विश्वविद्यालय की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। प्रतिवादी सं.5 और 6 की ओर से अर्थात विश्वविद्यालय की और से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता,श्री बिंध्याचल राय ने प्रस्तुत किया कि विश्वविद्यालय ने राज्यपाल सचिवालय द्वारा निर्गत निर्देशों के आलोक में कार्य किया है जैसा कि ज्ञापांक-948 दिनांक 18.06.2024 में निहित है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि पत्र संख्या बी. एस. यू. (वी. सी.)-45/2019 दिनांक 27.05.2020 में निहित दिशानिर्देश इस मामले में लागू नहीं होते है क्योंकि उक्त दिशानिर्देश उन मामलों के लिए हैं जहां किसी भी व्यक्ति के पर्यवसान करने का प्रस्ताव कुलपति के कार्यालय से निर्गत किया जाता है, जबकि तत्काल मामले में प्रतिवादी सं. 7 को सीधे माननीय कुलाधिपति द्वारा सीधे नियुक्त किया गया है, इसलिए प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का कोई उल्लंघन नहीं है।

13. प्रतिवादी संख्या 7, अर्थात वर्तमान कुलसचिव की ओर से एक जवाबी हलफनामा दायर किया गया है। श्री पवन कुमार द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरीय अधिवक्ता श्री संतोष कुमार ने प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से याचिकाकर्ता की प्रार्थना का विरोध किया।

14.विद्वान अधिवक्ता श्री पवन कुमार द्वारा सहायता प्राप्त विद्वान वरीय अधिवक्ता, श्री संतोष कुमार प्रतिवादी सं.7 की ओर से उपस्थित होकर प्रस्तुत किया कि,जैसा कि पत्र सं. बी. एस. यू. (वी. सी.)-45/2019 दिनांक 27.05.2020,में निहित दिशा निर्देश याचिकाकर्ता के मामले में लागू नहीं है क्योंकि उक्त दिशानिर्देश कुलपति के लिए हैं और यह बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 के तहत शक्ति का प्रयोग करते समय लागू नहीं होता है।

15. उन्होंने आगे कहा कि प्रतिवादी संख्या 7 का उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड है और वह रु 1,01,544 का सकल वेतन कम रहा है जो 7000 रुपये के ऐ जी पी से अधिक है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 की पात्रता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया है कि दिनांक 31.12.2008 के पत्र में निहित पात्रता मानदंड सीधी भर्ती के लिए है और इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 7 की नियुक्ति के मामले में प्रासंगिक नहीं है।

16. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि प्रतिवादी संख्या 7 की नियुक्ति बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 के अनुरूप की गई है और इस तरह की नियुक्ति के लिए पैनल के लिए अनुरोध अनिवार्य नहीं है। अपने तर्क को पुष्ट करने के लिए, प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 पर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित किया है और "हो सकता है" शब्द के उपयोग पर जोर दिया है यह दिखाने के लिए कि "हो सकता है "शब्द का उपयोग धारा 15 में कुलाधिपति को कुलसचिवों की नियुक्ति के लिए नामों के किसी भी पैनल के लिए अनुरोध करने का कोई आदेश नहीं मिलता है। वह ***भारतीय रिजर्व बैंक बनाम पीयरलेस जनरल फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट कंपनी लिमिटेड और अन्य, ए. आई. आर. 1987 एस. सी. 1023*** में प्रतिपादित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर निर्भर है। अनुच्छेद 37 में यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि,

> *"37. व्याख्या पाठ और संदर्भ पर निर्भर होनी चाहिए। वे व्याख्या के आधार हैं। कोई अच्छी तरह*

से कह सकता है कि यदि पाठ बनावट है, तो संदर्भ वह है जो रंग देता है। दोनों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। वह व्याख्या सबसे अच्छी है जो पाठ्य व्याख्या के सन्दर्भ से मेल खाती है। एक क़ानून की सबसे अच्छी व्याख्या तब की जाती है जब हम जानते हैं कि इसे क्यों लागू किया गया था। इस ज्ञान के साथ, क़ानून को पहले समग्र रूप से और फिर खंड दर खंड, खंड दर खंड, वाक्यांश दर वाक्यांश और शब्द दर शब्द पढ़ा जाना चाहिए। यदि किसी क़ानून को उसके अधिनियमन के संदर्भ में, ऐसे संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए क़ानून निर्माता के चश्मे के साथ देखा जाता है, तो उसकी योजना, धाराएं, खंड, वाक्यांश और शब्द रंग ले सकते हैं और संदर्भ द्वारा प्रदान किए गए चश्मे के बिना क़ानून को देखने पर अलग दिखाई दे सकते हैं। इन चश्मे के साथ हमें अधिनियम को पूर्ण रूप में देखना चाहिए और सम्पूर्ण अधिनियम की योजना उपयुक्त होने के लिए प्रत्येक धारा, प्रत्येक खंड, प्रत्येक वाक्यांश और प्रत्येक शब्द का क्या अर्थ है और क्या कहने के लिए परिकल्पित किया गया है,इसकी खोज करें। कानून के किसी भी हिस्से और कानून के किसी भी शब्द को अलग-अलग नहीं समझा जा सकता है। क़ानूनों की व्याख्या इस तरह से की जाना चाहिए कि हर शब्द का अपना एक स्थान हो और सबकुछ अपने स्थान पर हो। यह पूरे अधिनियम की स्थापना में समग्र रूप से परिभाषा को देखते हुए और अधिनियम से पहले की घटनाओं और इसके कारणों के संदर्भ में है कि न्यायालय ने श्रीनिवास में 'प्राइज चिट' अभिव्यक्ति की व्याख्या की और हमें न्यायालय की व्याख्या से अलग होने का कोई कारण नहीं मिलता है। "

17. प्रतिवादी संख्या *7* की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि याचिकाकर्ता को सेवा से पर्यवसित नहीं किया गया है, तथापि, उसे केवल बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 (3) (सी) के आधार पर स्थानांतरित किया गया है, जिसका उसके पद को कम करने या समाप्त करने का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इस तरह के स्थानान्तरण में प्राकृतिक न्याय का कोई उल्लंघन नहीं हो सकता है।

18. अदालत के इस प्रश्न पर कि यदि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया था तो कार्यमुक्त करने के आदेश में उस आदेश में धारा 15 (3) (सी) का उल्लेख क्यों नहीं किया गया, जिस पर विद्वान वरीय अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि कार्यमुक्त करने वाले आदेश सही रूप से धारा 15 का सही रूप से उल्लेख करता है, जैसा कि धारा 15 (3) (सी) धारा 15 के तहत आती है और यहां अन्यथा भी कानून के गलत प्रावधान का उल्लेख करना आदेश के लिए घातक नहीं होगा जब तक कि कुलाधिपति के पास हस्तांतरण करने की शक्ति है और प्रक्रियात्मक अशुद्धियाँ पर्याप्त न्याय पर हावी नहीं होंगी।

19. अंत में, प्रतिवादीसंख्या *7* की ओर से विद्वान वरीय अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया है कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 9 (7) (iii) के तहत उपलब्ध वैकल्पिक उपाय को देखते हुए रिट याचिका बनाए रखने योग्य नहीं है, जहां याचिकाकर्ता कुलाधिपति के समक्ष एक अभ्यावेदन दायर कर सकता है, यदि वह स्थानांतरण आदेश से व्यथित है और विद्वान वरीय अधिवक्ता ***राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य, ए. आई. आर. 2021 एस. सी. 2114*** में प्रतिपादित मामले में इस अदालत का ध्यान माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांतों पर आकर्षित करते हैं, जिसमें माननीय सर्वोच्च ने अभिनिर्धारित किया किः

> *"रिट याचिका पर विचार करने के लिए कानून के सिद्धांत जो उभर कर आते हैं वे ये हैंः*
>
> > *(i) संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट जारी करने की शक्ति का प्रयोग न केवल मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए किया जा सकता है, बल्कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए भी किया जा सकता है।*

(ii) उच्च न्यायालय को विवेकाधिकार है कि रिट याचिका ग्रहण ना करे उच्च न्यायालय की शक्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों में से वह एक है जहां व्यथित व्यक्ति के लिए एक प्रभावी वैकल्पिक उपचार उपलब्ध है;

(iii) वैकल्पिक उपचार के नियम के अपवाद तब उत्पन्न होते हैं जहां (क) संविधान के भाग III द्वारा संरक्षित मौलिक अधिकार के प्रवर्तन के लिए रिट याचिका दायर की गई है; (ख) प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन हुआ है; (ग) आदेश या कार्यवाही पूरी तरह से अधिकार क्षेत्र के बाहर हैं; या (घ) किसी विधि की वैधता को चुनौती दी गई है।

20. *इसके विपरीत,* याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि ज्ञापांक- बी. एस. यू. (रजिस्ट्रार)-06/2023-948 जी. एस. (आई) दिनांक 18.06.2024 और ज्ञापन सं. बी/1620 दिनांक 20.06.2024 को संयुक्त रूप से पढने से याचिकाकर्ता को बी. आर. ए., बिहार विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद से पर्यवसान करने का प्रभाव पड़ता है और केवल कार्यमुक्ति के वाक्यांश के उपयोग से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता श्री धनंजय कश्यप ने बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15(3) (सी) की ओर इस न्यायालय का ध्यान आकर्षित करते हुए कहा कि स्थानांतरण केवल समकक्ष पद पर ही किया जा सकता है। जबकि यह ऐसा मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को एक विश्वविद्यालय के कुलसचिव के पद पर दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, इस प्रकार 'कार्यमुक्त', 'स्थानांतरण' जैसे वाक्यांशों के उपयोग से उक्त आदेश का प्रभाव नहीं बदलेगा।

21. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि प्रतिवादीगण के अंत में दी गई दलीलें अंतर्निहित असंगति से ग्रस्त हैं क्योंकि एक ओर प्रतिवादीगण का कहना है कि आक्षेपित आदेश केवल एक स्थानांतरण है और दूसरी ओर, यह प्रस्तुत किया गया है कि उक्त आदेश याचिकाकर्ता के निष्पादन के उचित मूल्यांकन के बाद पारित किया गया है और उक्त आदेश विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक हित में पारित किया गया है। इस प्रकार, यदि याचिकाकर्ता के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था, तो याचिकाकर्ता से सुनवाई का अवसर नहीं छिना जा सकता है और इस तरह का एकतरफा और गुप्त मूल्यांकन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध है। याचिकाकर्ता के

लिए विद्वान अधिवक्ता प्रतिवादी संख्या 2 और 4 की ओर से दायर जवाबी हलफनामे के अनुच्छेद संख्या 8 पर अपनी प्रस्तुति का आधार बनाते हैं, जो इस प्रकार हैः

> *"8. यहां यह प्रस्तुत किया गया है कि निष्पादन मूल्यांकन के बाद याचिकाकर्ता को राज्यपाल सचिवालय की अधिसूचना (अनुलग्नक पी/1) की दिनांक 18.06.2024 के माध्यम से माननीय कुलाधिपति को विधि द्वारा प्रदत्त शक्ति के अंतर्गत तत्काल कार्यमुक्त करने का आदेश दिया गया था। "*

22. याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि "हो सकता है" वाक्यांश के उपयोग का मतलब यह नहीं है कि नियुक्ति पूर्णतः अपारदर्शी तरीके से की जा सकती है और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 में "हो सकता है" को "होगा" के रूप में पढ़ा जाना चाहिए। वह आगे प्रस्तुत करते हैं कि व्याख्या का नियम अनुमति देता है कि इसे किसी कानून के पीछे के विधायी आशय को आगे बढ़ाने के लिए "सकता है" को "होगा" पढ़ा जा सकता है और वे ***मोहन सिंह और अन्य बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा प्राधिकरण (1997) 9 एस. सी. सी. 132*** में प्रतिपादित मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विश्वास करते हैं,जहाँ अनुच्छेद 17 में यह प्रतिपादित किया गया था कि,

> *"17. भाषा के अनिवार्य अनुपालन या निर्देशिका के प्रभाव का अंतर विचाराधीन क़ानून में दी गई भाषा और उसके उद्देश्य, प्रयोजन और प्रभाव पर निर्भर करता है। "होगा" या "हो सकता है" शब्द के उपयोग में परिलक्षित अंतर शक्ति प्रदान करने पर निर्भर करता है। वर्तमान संदर्भ में, "सकता है" का अर्थ हमेशा सकता है नहीं होता है। प्रावधान के अनुपालन को सक्षम करने के लिए सकता है एक अनिवार्य शर्त है, लेकिन ऐसे मामले हैं जिनमें, विभिन्न कारणों से, जैसे ही किसी व्यक्ति को जो कानून के दायरे में आता है उसे शक्ति सौंपी जाती है, उसका प्रयोग करना कर्तव्य बन जाता है। जहाँ कानून की भाषा एक कर्तव्य का निर्माण करती है, वहाँ कर्तव्य के गैर-निष्पादन के लिए विशेष उपाय निर्धारित किया जाता है। "रेज ऑन*

स्टेच्यूट लॉ " (7 वें संस्करण) में यह कहा गया है कि न्यायालय, एक सामान्य नियम के रूप में यह मान लेगा कि कार्रवाई के लिए सामान्य कानून या परमादेश द्वारा उचित उपचार लागू करने का इरादा था। कानून का सामान्य नियम यह है कि जहां कानून द्वारा एक सामान्य दायित्व बनाया जाता है और उल्लंघन के लिए वैधानिक उपचार प्रदान किया जाता है, तो वैधानिक उपचार अनिवार्य है। हालांकि कानून का दायरा और भाषा और कभी-कभी नीति का विचार अपवाद पैदा कर सकता है, जो यह दर्शाता है कि विधायिका का इरादा किसी उपाय (व्यापकता) को अनन्य होने का नहीं था। शब्द भाषा की त्वचा हैं। भाषा उस इरादे और उद्देश्य को व्यक्त करने का माध्यम है जिसे विशेष प्रावधान या अधिनियम प्राप्त करना चाहता है। इसलिए, इरादे का पता लगाना आवश्यक है। "होगा" शब्द हमेशा निर्णायक नहीं होता है। यह निर्धारित करने में कि क्या यह अनिवार्य है या निर्देशिका है,प्रश्न में वैधानिक प्रावधान के संदर्भ, विषय वस्तु और उद्देश्य को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस सन्दर्भ में कानून का कोई सार्वभौमिक सिद्धांत नहीं रखा जा सकता कि क्या कोई विशेष प्रावधान या अधिनियम को अनिवार्य या निर्देशिका माना जाएगा। यह न्यायालय का कर्तव्य है कि वह विचाराधीन क़ानून या धारा या एक वाक्यांश के सम्पूर्ण दायरे का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करके विधायिका के वास्तविक इरादे को प्राप्त करने का प्रयास करे। जैसा कि पहले कहा गया है, यह सवाल कि क्या क़ानून अनिवार्य है या निर्देशिका विधायिका के इरादे पर निर्भर करती है, न कि हमेशा उस भाषा पर जिसमें इरादे को व्यक्त किया जाता है। विधायिका का अर्थ और मंशा उस अधिनियम की रूपरेखा और उद्देश्य को नियंत्रित करेगा जिसे वह प्राप्त करना चाहता है। अनुच्छेद 316 में पेज

81 पर "सदरलैंड सांविधिक निर्माण" (तीसरा संस्करण) खंड I में कहा गया है कि हालांकि अनिवार्य और निर्देशिका कानून की समस्या सभी सरकारी गतिविधियों के लिए खतरा है, लेकिन यह विशेष रूप से प्रशासनिक संगठनों के लिए खतरनाक है क्योंकि उनकी कार्रवाई की वैधता उनके अस्तित्व के चार्टर कानून के अनुसार अधिकार के प्रयोग पर निर्भर करती है। यदि कानून के निर्देश अनिवार्य हैं, तो प्रशासनिक कार्रवाई की वैधता के लिए वैधानिक शर्तों का सख्ती से अनुपालन आवश्यक है। लेकिन अगर क़ानून की भाषा केवल निर्देशिका है, तो इसके निर्देश से भिन्नता प्रशासनिक कार्रवाई को अमान्य नहीं करती है। इसके विपरीत, यदि वैधानिक निर्देश केवल विवेकाधीन है, यह विधायी कार्रवाई और प्रत्यायोजन के लिए पर्याप्त मानक प्रदान नहीं कर सकता है। पृष्ठ 516 पर "क्रॉफर्ड ऑन द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टैचूट्स" में कहा गया है किः यह प्रश्न कि क्या कोई क़ानून अनिवार्य है या निर्देशिका विधायिका के इरादे पर निर्भर करती है न कि उस भाषा पर जिसमें इरादे को व्यक्त किया गया है। विधायिका के अर्थ और इरादे को नियंत्रित करना चाहिए, और इन्हें न केवल प्रावधान के शब्दावली से, बल्कि इसकी प्रकृति, इसकी रूपरेखा और इसके किसी न किसी रूप में अर्थ लगाने से होने वाले परिणामों पर विचार करके भी निर्धारित किया जाना चाहिए।

23. अपने प्रस्तुति को पुष्ट करने के लिए, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता प्रस्तुत करते हैं कि यह कानून का सामान्य सिद्धांत है कि जब क़ानून स्पष्ट रूप से किसी प्रक्रिया का पालन करने का आदेश देता है, तो उसे उस विशेष तरीके से करने की आवश्यकता होती है या बिल्कुल नहीं किया जाता है। वह ***नज़ीर अहमद बनाम किंग इम्पेरर, 1936 एस. सी. सी. ऑनलाइन पी. सी. 41*** में प्रिवी काउंसिल के फैसले पर विश्वास करते हैं। जिसमें यह अभिनिर्धारित किया गया था कि *"जहां किसी विशेष कार्य को एक निश्चित तरीके से करने की शक्ति दी जाती है, वह कार्य उस तरह से किया*

जाना चाहिए या बिल्कुल नहीं। निष्पादन के अन्य तरीकों को अनिवार्य रूप से प्रतिबंधित किया गया है। "

24. वह ***चेरुकुरी मणि बनाम मुख्य सचिव, आंध्र प्रदेश सरकार और अन्य, (2015) 13 एस. सी. सी. 722,*** के मामले पर भी विश्वास करते हैं। जिसमें माननीय उच्चतम न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि *"जहाँ कानून एक विशेष प्रक्रिया का पालन करते हुए एक विशेष तरीके से किया जाने वाला काम निर्धारित करता है, वह उसे निर्धारित प्रक्रिया से विचलित हुए बिना, कानून के प्रावधानों का पालन करते हुए उसी तरीके से किया जाएगा।*

25. अंत में, याचिकाकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से वैकल्पिक उपचार की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए रिट याचिका की स्थिरता से संबंधित प्रस्तुतिकरण का खंडन करते हुए कहा कि ***राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य। (ऊपर)*** के मामले में प्रतिपादित सिद्धांत यह प्रदान करता है कि प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के मामले में रिट बनाए रखने योग्य है और यह याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला है कि उसे प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन में समाप्त कर दिया गया है।

26. पक्षों की ओर से अग्रिम प्रस्तुतिकरण पर विचार करने के बाद, मैं याचिकाकर्ता के लिए विद्वान अधिवक्ता के प्रस्तुतिकरण में बल पता हूँ कि तत्काल रिट बनाए रखने योग्य है क्योंकि याचिकाकर्ता का विशिष्ट मामला प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन का है। यह अब और अधिक महत्वपूर्ण नहीं है कि, वैकल्पिक उपाय की उपलब्धता एक स्व-अधिरोपित प्रतिबंध है और यह कोई बाध्यता नहीं है जैसा कि ***व्हर्लपूल कॉर्पोरेशन बनाम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रार, मुंबई (1998) 8 एस. सी. सी. 1*** में निष्पादित साथ-साथ ***राधा कृष्ण इंडस्ट्रीज बनाम हिमाचल प्रदेश राज्य और अन्य (ऊपर)*** के मामले में अभिनिर्धारित किया गया है।

27. अब, याचिकाकर्ता की सेवा समाप्ति के मुद्दे पर प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, मुझे बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 7, धारा 8, धारा 15 (1) और 15 (3) (सी) को पुनः प्रस्तुत करना उचित लगता है, जिसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया हैः

> 7. **विश्वविद्यालय के अधिकारी**-विश्वविद्यालय के अधिकारी निम्नलिखित होंगे -
>
> (1) कुलपति

(2) उपकुलपति

(3) प्रतिकुलपति

(4) वित्तीय सलाहकार

(5) संकाय अध्यक्ष, छात्र कल्याण

(6) कुलानुशासक

(7) कुलसचिव

(8) महाविद्यालय निरीक्षक

(9) वित्त अधिकारी, और

(10) ऐसा अन्य व्यक्ति या व्यक्ति जिसे क़ानूनों द्वारा विश्वविद्यालय का अधिकारी घोषित किया जा सके।

8. **अधिकारियों का स्थानांतरण**-के अधिकारी - धारा 7 की क्रमिक सं. 4 से 9 के अंतर्गत विश्वविद्यालय के अधिकारीयों को कुलाधिपति द्वारा या किसी **अन्य समकक्ष पद पर किसी अन्य विश्वविद्यालय** में या विश्वविद्यालय के भीतर किसी अन्य समकक्ष पद पर स्थानांतरित किया जा सकता है।

15. कुलसचिव– **(1)** अधिनियम के किसी भी प्रावधान के बावजूद, यदि कुलाधिपति उचित समझते है, तो वे राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या किसी भी विश्वविद्यालय से कुलसचिव के पद के लिए बिहार प्रशासनिक सेवाओं के सेवानिवृत्त अधिकारियों सहित उपयुक्त अधिकारियों के नाम भेजने का अनुरोध कर सकते हैं और उस स्थिति में राज्य सरकार, केंद्र सरकार, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग या कोई भी विश्वविद्यालय एक या एक से अधिक अधिकारियों के नाम ऐसे सेवा नियमों और शर्तों के तहत कुलसचिव के रूप में नियुक्ति के लिए विचार के लिए भेज सकता है, जो वे उचित समझें, और फिर कुलाधिपति उनमें से कुलसचिव की नियुक्ति करेंगे।

(2) कुलसचिव विश्वविद्यालय का पूर्णकालिक अधिकारी होगा और वह सीनेट, सिंडिकेट और अकादमिक परिषद के सचिव के रूप में कार्य करेगा औरः.

(क) अभिलेखों, सामान्य मुहर और ऐसी अन्य संपत्तियों का संरक्षक होगा। कुलपति के रूप में विश्वविद्यालय और सिंडिकेट उनके प्रभार के लिए प्रतिबद्ध होंगे।

(ख) विश्वविद्यालय के आधिकारिक पत्राचार का संचालन करेगा, और विश्वविद्यालय के उचित निवेश को बनाए रखेगा;

(ग) ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करें जो संविधि में विनिर्दिष्ट किए गए हों या अध्यादेश या विनियमन द्वारा निर्धारित किए गए हों या जो कुलपति, उप-कुलपति या सिंडिकेट द्वारा समय-समय पर अपेक्षित हों।

(घ) विश्वविद्यालय द्वारा या उसके विरुद्ध मुकदमों या कार्यवाही में विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व करना, अधिवक्ता की शक्तियों पर हस्ताक्षर करना और अभिवचनों को सत्यापित करना या इस प्रयोजन के लिए अपने प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त करना;

(ङ) परीक्षा के संचालन और परिणामों के प्रकाशन के संबंध में अपने कर्तव्यों के निर्वहन में कुलपति और उप-कुलपति को सहायता प्रदान करना;

(च) विश्वविद्यालय के घटक महाविद्यालयों और विभागों के अलावा अन्य संबद्ध संस्थानों का उचित देखभाल करना और कुलपति को रिपोर्ट करेगा;

(छ) अनुसचिवीय कर्मचारियों से सम्बन्धित कर्मचारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने और उन्हें चेतावनी देने या उन पर निंदा का जुर्माना लगाने या वेतन वृद्धि को रोकने के लिए जांच लंबित रहने तक उन्हें निलंबित करने की शक्ति हैः

बशर्ते कि ऐसा कोई जुर्माना तब तक नहीं लगाया जाएगा जब तक कि संबंधित व्यक्ति को उसके खिलाफ की जाने वाली प्रस्तावित कार्रवाई के खिलाफ कारण दिखाने का उचित अवसर नहीं दिया गया हो।

(3)(क).....

(ख)....

(ग) कुलसचिव को **कुलाधिपति द्वारा** एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में उसी या **किसी समकक्ष पद पर स्थानांतरित** किया जा सकता है

(जोर दिया गया)

28. बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की योजना, विशेष रूप से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 7 और धारा 15 (2) की बारीकी से जांच से यह स्पष्ट होगा कि कुलसचिव के पद की पहचान विश्वविद्यालय के अधिकारी के रूप में की गई है। कुलसचिव का पद न केवल एक प्रतिष्ठित पद है, बल्कि यह महत्वपूर्ण प्रशासनिक कार्यों के निर्वहन, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के साथ-साथ प्रतिनिधि चरित्र की कार्यक्षमता का प्रतीक है। यह उच्च जवाबदेही और उच्च जिम्मेदारी वाला पद है। इसी तरह, यदि कुलसचिव का पद किसी विश्वविद्यालय के लिए महत्वपूर्ण है, तो नियुक्ति के साथ-साथ समाप्ति भी एक निर्धारित प्रक्रिया के अंतर्गत की जानी चाहिए और यह अपारदर्शिता और व्यक्तिपरकता की छाया में जल्दबाजी का कार्य नहीं हो सकता है।

29. मुझे प्रतिवादियों के इस तर्क में कोई बल नहीं मिलता कि याचिकाकर्ता का स्थानांतरण किया गया था और इसलिए, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। प्रतिवादियों के इस तर्क को अस्वीकार करने का स्पष्ट कारण बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम की धारा 8 और धारा 15 (3) (सी) से निकलता है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 के उक्त प्रावधानों के अवलोकन से, विधायी इरादा स्पष्ट हो जाता है कि "स्थानांतरण" में "पद की समतुल्यता" की पूर्वधारणा है और यह मामला नहीं है कि याचिकाकर्ता को बी. आर. ए. बिहार विश्वविद्यालय से कुलसचिव के पद पर किसी अन्य विश्वविद्यालय में स्थानांतरित कर दिया गया है, जबकि मामला यह है कि प्रतिवादी संख्या 7 को याचिकाकर्ता के स्थान पर नियुक्त किया गया है और फिर याचिकाकर्ता को हाजीपुर में

पदस्थापित किया गया है, इस प्रकार कुलसचिव के पद की समानता को बनाए नहीं रखना यह दर्शाता है कि यह सीधे तौर पर स्थानांतरण का मामला नहीं है।

30. प्रत्यर्थियों के तर्क को अस्वीकार करने का एक अन्य कारण प्रतिवादी संख्या 2 और 4 द्वारा प्रस्तुत प्रस्तुतियों से आता है, जिसमें उनकी ओर से यह प्रस्तुत किया गया है कि याचिकाकर्ता के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था और फिर विश्वविद्यालय के शैक्षणिक और प्रशासनिक हित में याचिकाकर्ता को कुलसचिव के पद से हटाने का निर्णय लिया गया था। प्रतिवादी सं.2 और 4 के प्रस्तुतियों पर विचार करने पर यह पस्र चलता है कि याचिकाकर्ता को उसके निष्पादन के मूल्यांकन के आधार पर कुलसचिव के पद से समाप्त/हटा दिया गया है और इस तरह के कार्य को कार्यमुक्त या स्थानांतरण जैसे हानिरहित वाक्यांशों के उपयोग से बचाया नहीं जा सकता है और यह निश्चित रूप से बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 (3) (सी) के तहत स्थानांतरण का मामला नहीं बनता है।

31. यह स्थापित कानून है कि कार्यमुक्त जैसे वाक्यांशों के उपयोग से हानिरहित अभिव्यक्तियाँ आदेश की प्रकृति को नहीं बदलती हैं और आदेश की जांच के लिए वास्तविक परीक्षण यह देखना है कि क्या इस तरह के आदेश के साथ सेवा करने वाले व्यक्ति को किसी नुकसान या कलंक का सामना करना पड़ता है और यदि उत्तर सकारात्मक है तो इस तरह के आदेश को स्थापित प्रक्रियाओं के साथ-साथ प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का सख्ती से पालन करते हुए पारित किया जाना चाहिए। निष्पादन के मूल्यांकन पर याचिकाकर्ता को हटाने और हाजीपुर में तत्काल स्थानांतरण एक कलंक ले जाने के लिए बाध्य है जिसका याचिकाकर्ता के करियर पर निश्चित प्रभाव पड़ेगा। इस प्रकार, याचिकाकर्ता को कार्यमुक्त करने के आदेश को केवल हानिरहित अभिव्यक्तियों के उपयोग से नहीं बचाया जा सकता है। यह स्वीकृत स्थिति है कि याचिकाकर्ता को बिना किसी पूर्व कारण बताओ या किसी भी तरह से किसी भी सूचना के ज्ञापांक बी/1620 दिनांक 20.06.24 के साथ मुलाकात की गई थी, इस प्रकार यह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के स्पष्ट उल्लंघन का मामला है जहां याचिकाकर्ता के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया है और उसे हटा दिया गया है लेकिन उसे सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया गया और कार्यमुक्त करने की हानिरहित अभिव्यक्ति ज्ञापांक बी/1620 दिनांक 20.06.24 को प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का उल्लंघन करने से नहीं बचाती है।

32. इसके अलावा, याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत पत्र संख्या-बी. एस. यू. (वी. सी.)-45/2019 दिनांक 27.05.2020, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का अवलोकन करके

कुलसचिव को बर्खास्त करने के लिए एक विस्तृत प्रक्रिया प्रदान करता है। मुझे दिनांक 27.05.2020 के पत्र की विषय-वस्तु को यहाँ नीचे पुनः प्रस्तुत करना उपयुक्त लगता है:

> यह देखा गया है कि ***कुलपति सचिवालय में विश्वविद्यालयों के अधिकारियों की नियुक्ति की समाप्ति के लिए कुलपतियों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं*** जिन्हें माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से नियुक्त किया गया है।

इस संबंध में, मुझे यह सूचित करने का निर्देश हुआ है कि माननीय कुलाधिपति नें, का समुचित विचार करने और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 9 (7) (ii) और पटना विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 10 की उप-धारा (7) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्राकृतिक न्याय के हित में, यह आदेश देने के की कृपा की है कि यदि बिहार में किसी विश्वविद्यालय का कुलपति अपने विश्वविद्यालय में एक अधिकारी के कामकाज से संतुष्ट नहीं है, जिसे माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से नियुक्त किया गया है, उदाहरण के लिए वित्तीय सलाहकार, ***कुलसचिव,*** वित्त अधिकारी आदि के कामकाज़ से संतुष्ट नहीं है और ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति को समाप्त करना विश्वविद्यालय के शैक्षणिक या प्रशासनिक हित में मानता है, ***तो उसे सबसे पहले उक्त अधिकारी से अधिकारी के खिलाफ आरोपों के बयान के साथ स्पष्टीकरण/कारण बताओ मांगना चाहिए और उसे स्पष्टीकरण/कारण बताओ प्रस्तुत करने के लिए उचित समय प्रदान करना चाहिए, जो आम तौर पर 7 दिनों से कम नहीं होना चाहिए***(जब तक कि यह बहुत तात्कालिकता का मामला न हो)। इसके बाद, यदि कुलपति अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण/कारण-बताओ से संतुष्ट नहीं हैं ***तो वह अधिकारी की नियुक्ति को समाप्त करने के संबंध में प्रस्ताव भेज सकते हैं साथ हीं वह अधिकारी द्वारा प्रस्तुत स्पष्टीकरण/कारण बताओ पर अपनी टिप्पणियों और की जाने वाली कार्रवाई के सम्बन्ध में स्पष्ट सिफारिश भी माननीय कुलाधिपति के आदेश हेतु भेज सकते हैं।***

(जोर दिया गया**)**

33. ऊपर दी गई प्रक्रिया की बारीकी से जाँच से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है किः

I. यह प्रक्रिया विश्वविद्यालय में कुलसचिव सहित किसी भी अधिकारी पर लागू होती है, जिसे माननीय कुलाधिपति के अनुमोदन से नियुक्त किया गया है।

II. यदि कुलपति के पास यह मानने के कारण हैं कि ऐसे अधिकारी की बर्खास्तगी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक या प्रशासनिक हित में है, तो

III. कम से कम 7 दिनों के समय के साथ एक कारण बताओ जारी किया जाना चाहिए, जबकि ऐसे 7 दिनों के समय को बहुत तात्कालिकता के मामलों में हटाया जा सकता है।

IV. यदि उप कुलपति स्पष्टीकरण से संतुष्ट नहीं हैं, तो माननीय कुलाधिपति के आदेश के लिए अपनी टिप्पणियों के साथ संस्तुति प्रस्तुत की जा सकती है।

34. इस न्यायालय की राय है कि यदि कोई निर्धारित प्रक्रिया है,किसी व्यक्ति को कुलसचिव के पद से बर्खास्तगी के लिए, तो ऐसी प्रक्रिया को केवल यह कहकर दरकिनार नहीं किया जा सकता है कि यह प्रक्रिया कुलाधिपति द्वारा दिए गए आदेशों पर लागू नहीं होती है क्योंकि यह प्रक्रिया कुलाधिपति द्वारा की गई सिफारिशों के लिए लागू होती है। यदि इसे स्वीकार कर लिया जाता है तो निर्धारित प्रक्रिया बस एक दिखावा बनकर रह जाएगा जिसका उपयोग सुविधा के अनुसार और अस्वीकार किया जा सकता है। इस प्रक्रिया को अनिवार्य ठहराने का एक अन्य कारण यह है कि पूरी प्रक्रिया कुलाधिपति को इस निष्कर्ष पर पहुंचने में सुविधा प्रदान करने के लिए है कि यदि किसी व्यक्ति को सहायक सामग्री के साथ आरोप और स्पष्टीकरण के विवरण पर विचार करने के बाद कुलसचिव आदि के पद से बर्खास्त किया जा सकता है, ताकि यह सुनिश्चित करने के लिए कि एक सूचित निर्णय लिया गया है, जो पीड़ित को कुलाधिपति के समक्ष प्रस्तुत सामग्री में दोष दिखाकर ऐसी सिफारिश के खिलाफ कुलाधिपति के पास जाने का एक प्रभावी उपाय भी प्रदान करेगा। हालाँकि, यदि इस प्रक्रिया को कुलाधिपति द्वारा दिए गए आदेशों पर लागू नहीं माना जाता है, तो इसका दुरुपयोग किया जा सकता है और पीड़ित व्यक्ति उपचार से वंचित रह जाएगा।

35. प्रतिवादियों का तर्क कि यह प्रक्रिया माननीय कुलाधिपति पर लागू नहीं होती है, एक स्पष्ट कारण से खारिज किया जा सकता है कि यदि एक विस्तृत प्रक्रिया माननीय कुलाधिपति को निर्णय लेने में सुविधा प्रदान करने के लिए बनाई गई है,तो सामग्री प्रदान करके ऐसी सुविधा के अभाव में, निर्णय गैर-वाचनात्मक और कारणों से रहित होना बाध्य है जैसा की तत्काल मामले में हुआ है। साथ हीं, यदि याचिकाकर्ता के निष्पादन का मूल्यांकन किया गया था, तो याचिकाकर्ता को इस तरह के मूल्यांकन पर सुनवाई करने का अधिकार है और प्रतिवादी संख्या 2 और 4 द्वारा तत्काल कार्यवाही के दौरान इस तरह के मूल्यांकन के किसी भी विवरण को प्रस्तुत नहीं करना स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कथित मूल्यांकन कुछ भी नहीं, बल्कि एक गैर-वाचनात्मक आदेश को बचाने का एक कमजोर प्रयास है।

36. पत्र संख्या- बीएसयू (वीसी)-45/2019 दिनांक 27.05.2020 में निहित प्रक्रिया की प्रयोज्यता के बारे में प्रतिवादियों के तर्क को अस्वीकार करने का एक और कारण यह है कि यदि इस तरह के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया जाता है तो यह एक ऐसी प्रक्रिया को जन्म देगा जो बिल्कुल अपारदर्शी और व्यक्तिपरक होगी जो किसी भी क़ानून की मंशा नहीं हो सकती है और इस तरह के प्रस्ताव को किसी भी विश्वविद्यालय के शैक्षणिक या प्रशासनिक हित में नहीं कहा जा सकता है।

37. अब, प्रतिवादी संख्या 7 की नियुक्ति पर आते हैं। मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, भारत सरकार द्वारा निर्गत पत्र दिनांक 31.12.2006 और मानव संसाधन विकास विभाग, बिहार सरकार द्वारा निर्गत संकल्प संख्या 15/डी 1-01/09 अंश-II उ०शि० 2693 दिनांक 27.08.2009 के अवलोकन में, यह देखा जा सकता है कि कुलसचिव के पद के लिए निर्धारित पात्रता मानदंड रु 7, 000 और उससे अधिक के ऐ जी पी में सहायक प्रोफेसर के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव है, या 8000 रु और उससे अधिक के ऐ जी पी में सहायक प्रोफेसर या 8 साल की सेवा के साथ शैक्षिक प्रशासन में अनुभव के साथ एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में सेवा शामिल है, हालांकि, प्रतिवादी संख्या 7 यह दिखाने में विफल रहा है कि प्रतिवादी संख्या 7 के पास ऐसी पात्रता है। इस बिंदु पर, यह दर्ज करना भी बहुत महत्वपूर्ण है कि प्रतिवादी संख्या 7 का कोई नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है जो मूल तक जाता है और प्रतिवादी संख्या 7 के दावे को गंभीर रूप से प्रभावित करता है। नियुक्ति पत्र प्रस्तुत करने के बजाय, एक प्रमाण पत्र दिखाने का प्रयास किया जाता है कि प्रतिवादी संख्या 7 पटना महिला महाविद्यालय में भौतिकी विभाग में सहायक प्रोफेसर के रूप में काम कर रही है और एक पुष्टिकरण पत्र जिसे किसी भी परिस्थिति में नही कहा जा सकता

सकता की प्रतिवादी संख्या 7 विचार के लिए भी योग्य हैं। प्रतिवादी सं.7 द्वारा प्रतिवादी सं.7 के सकल वेतन और उत्कृष्ट शैक्षणिक रिकॉर्ड के बारे में उठाया गया तर्क भी गलत है क्योंकि प्रतिवादी सं.7 के शैक्षणिक रिकॉर्ड या वेतन की मात्रा के बारे में कोई प्रश्न नहीं है, जबकि एकमात्र पात्रता सहायक प्राध्यापक/सह-प्राध्यापक के रूप में अनुभव और 7000 या 8000 के ऐ जी पी जैसा भी मामला हो,के बारे में है, इसलिए प्रतिवादी संख्या 7 का तर्क खारिज़ करने योग्य है।

38. अब, जहाँ तक, प्रतिवादी सं.7 की नियुक्ति की प्रक्रिया से संबंध है, प्रतिवादी संख्या 2 और 4 यह दिखाने में विफल रहे हैं कि नामावली के लिए कोई भी अनुरोध माननीय कुलाधिपति द्वारा बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 में किए गए वैधानिक प्रावधान के अनुरूप पूर्व में कभी भी किया गया था। इसके अलावा, प्रतिवादी सं.7 द्वारा उठाए गए तर्क के संबंध में कि ऐसा अनुरोध अनिवार्य नहीं है क्योंकि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 में "सकता है" वाक्यांश का उपयोग किया गया है और इसमें "होगा" शब्द का उपयोग नहीं किया गया है, यह पूरी तरह से गलत है और बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 की गलत व्याख्या पर आधारित प्रतीत होता है।

39. व्याख्या के नियम की यह स्थापित स्थिति है कि विधि के आशय के आधार पर 'may' का प्रयोग 'shall' के रूप में किया जा सकता है तथा 'shall' का प्रयोग 'may' के रूप में किया जा सकता है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 पर व्याख्या के इस नियम को लागू करते हुए, मैं पाता हूँ कि यदि 'may' वाक्यांश को केवल निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाए तो ऐसी व्याख्या से व्यक्तिपरकता और अपारदर्शिता की गुंजाइश पैदा होगी। पैनल की मांग के लिए प्रक्रिया निर्धारित करने का आशय नियुक्ति की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी बनाता है तथा यह सुनिश्चित करता है कि विभिन्न हितधारकों के पास सुझाव देने के लिए है ताकि नियुक्ति योग्य उम्मीदवारों के पैनल से की जा सके, जबकि दूसरी ओर यदि ऐसी प्रक्रिया को केवल निर्देशिका तक सीमित कर दिया जाए तो ऐसी प्रक्रिया हमेशा दुरुपयोग के लिए खुली रहेगी, जबकि कोई भी नियुक्ति पूर्णतः अपारदर्शी और व्यक्तिपरक तरीके से की जा सकती है। दोनों प्रस्तावों पर विचार करने के बाद, मेरी राय है कि इस क़ानून का उद्देश्य नियुक्ति की अपारदर्शी प्रथा या प्रक्रिया को प्रोत्साहित करना नहीं हो सकता, जबकि क़ानून की असली भावना पारदर्शिता सुनिश्चित करना है जो संबंधित विश्वविद्यालय के सर्वोत्तम शैक्षणिक हित में भी है। ***मोहन सिंह और अन्य बनाम भारतीय अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा***

प्राधिकरण और अन्य (ऊपर) के मामले पर पहले ही पिछले पैराग्राफ में चर्चा की जा चुकी है।

40. यदि प्रतिवादियों की यह दलील स्वीकार कर ली जाए कि तब ऐसी ही स्थिति उत्पन्न हो सकती है जैसी कि वर्तमान मामले में उत्पन्न हुई है, जहां किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए कोई ठोस कारण न होने अथवा यह दर्शाए बिना कि ऐसे व्यक्ति को पद के लिए क्यों विचार किया गया, आदेश पारित किया जा सकता है। मेरी राय में प्रतिवादियों की दलीलें इस प्रकार खारिज किए जाने योग्य हैं, जैसे कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 में 'may' का प्रयोग केवल निर्देशिका के रूप में पढ़ा जाए, तो ऐसी व्याख्या विधि के उद्देश्य और भावना के विपरीत होगी और इसलिए मैं मानता हूं कि बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 में 'may' का प्रयोग अनिवार्य प्रकृति का है।

41. उपर्युक्त पैराग्राफ में वर्णित तथ्यात्मक और कानूनी पहलुओं के मद्देनजर, मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि याचिकाकर्ता को बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पद से मुक्त करना माननीय कुलाधिपति कार्यालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार प्रदान की गई प्रक्रिया की पूर्ण अवहेलना करते हुए हटाने/समाप्त करने के समान है और इस तरह यह कानून की दृष्टि से गलत है और साथ ही प्रतिवादी संख्या 7 को बीआरए के रजिस्ट्रार के रूप में उनकी जगह नियुक्त करना भी गलत है। बिहार राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1976 की धारा 15 में निहित वैधानिक अनिवार्य आवश्यकता का घोर उल्लंघन करते हुए अयोग्य होने के बावजूद बिहार विश्वविद्यालय द्वारा उनके खिलाफ दायर किया गया आरोप कानून की दृष्टि में टिकने योग्य नहीं है और इस प्रकार ज्ञापन संख्या बीएसयू (रजिस्ट्रार)-06/2023-948/जीएस(आई) दिनांक 18.06.2024, ज्ञापन संख्या बी/1612 दिनांक 19.06.24 और ज्ञापन संख्या बी/1620 दिनांक 20.06.2024 में निहित उपरोक्त दोनों आदेश एतद्द्वारा रद्द और अपास्त किए जाते हैं और याचिकाकर्ता को तदनुसार तत्काल प्रभाव से बीआरए बिहार विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार के पद पर बहाल किया जाता है।

42. परिणामस्वरूप, रिट याचिका को उपरोक्त शर्तों के अनुसार स्वीकार किया जाता है, लेकिन लागत के संबंध में कोई आदेश नहीं दिया जाता है।

(अंजनी कुमार शरण, न्यायमूर्ति)

त्रिवेदी/-

खंडन (डिस्क्लेमर)- स्थानीय भाषा में निर्णय के अनुवाद का आशय, पक्षकारों को इसे अपनी भाषा में समझने के उपयोग तक ही सीमित है और अन्य प्रयोजनार्थ इसका उपयोग नही किया जा सकता। समस्त व्यवहारिक, कार्यालयी, न्यायिक एवं सरकारी प्रयोजनार्थ, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रमाणिक होगा साथ ही निष्पादन तथा कार्यान्वयन के प्रयोजनार्थ अनुमान्य होगा।